

tance of about Rs. 12 crores will be provided for the development of irrigation in tribal areas. The drought prone areas programme is also being implemented specially to cater to the needs of the backward areas. Under this programme as well irrigation has been given high priority.

Slums

2630. SHRI P. KANNAN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether any new strategy has been evolved for purposeful implementation by all States to arrest the proliferation and density of slums; and

(b) the review of all measures taken so far and the impact achieved for containing the problem?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) (a) No, Sir.

(b) No such review has been undertaken.

Assistance to States for construction of Working Women Hostels

2631. SHRIMATI BIBHA GHOSH GOSWAMI: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have offered assistance to the State Governments to the tune of 75 per cent of the cost of construction of hostels for working women;

(b) if so, number and names of the States which have been offered the assistance; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE

(DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) No, Sir. Financial assistance to the extent of 75 per cent of the cost of construction, under Working Women's Hostels Scheme, is given to voluntary organisations.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी द्वारा भारत को छात्रवृत्तियां

2632. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी द्वारा भारत को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

(ख) क्या सरकार इस प्रकार की छात्रवृत्तियों का उचित उपयोग करती है; और

(ग) क्या इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया अनुकूल है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी) (क) से (ग) जी, हा।

जम्मू में गोदारों में चावल नष्ट होना

2633. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू में गोदारों में हजारों टन चावल नष्ट हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और क्या उसके लिए सरकारी अधिकारी उत्तरदायी थे, और

(ग) यदि हाँ, तो वे भी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। 1977-78 के दौरान अन्य क्षेत्रों से प्राप्त भोगे हुए स्टाक की मफाई करने के बाद केवल 96 मीटरी टन चावल क्षतिग्रस्त पाया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राजस्थान में विश्व बैंक की सहायता से बीजों का उत्पादन

2634. श्री चतुर्भोज : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम विश्व बैंक की सहायता में पांच राज्यों में उन्नत बीजों का उत्पादन करने की योजना बना रहा है और इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा क्या है,

(ख) राजस्थान में इस काम के लिए चुने जाने वाले स्थानों के नाम और उन पर खर्च होने वाली रकम, उत्पादन किए जाने वाले बीजों की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम में उत्पादकों को भी सम्बद्ध कर उन्हें हिस्सा दिया जाएगा?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) में (ग) प्रमाणीकृत

बीज उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और राजस्थान में परियोजनाएं तैयार की हैं। विश्व बैंक द्वारा इनका मूल्यांकन किया गया है। राजस्थान सरकार का इन्हीं के समान एक राजकीय बीज निगम की स्थापना करने का विचार है जो कि अन्य राज्यों में पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। यह बीज निगम कोटा, बूंदी और श्रीगंगा नगर जिलों के चुने हुए परियोजना क्षेत्रों से प्रमाणीकृत बीजों का उत्पादन करेगा। चूंकि भारत सरकार इस परियोजना पर अन्य राज्यों की परियोजनाओं के साथ विचार कर रही है, अतः इस स्थिति में व्यय को जाने वाली धनराशि और राजस्थान में पैदा किए जाने वाले बीजों की मात्रा के संबंध में ठीक-ठीक आंकड़े नहीं बताए जा सकते। विचार है कि प्रस्तावित निगम के 35 प्रतिशत शेयर बीज उत्पादकों के होंगे।

Posts of Investigators in the Town and Country Planning Organisation

2635 SHRIM A HANNAN ALHAJ: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) whether some UDCs have been officiating as Head Clerks in the Town and Country Planning Organisation against the vacant posts of Investigators,

(b) whether the Technical work of the Organisation has not been suffering due to non-filling up of the posts of Investigators, and

(c) if so, the immediate steps taken by the Organisation to fill up these posts?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Yes, Sir